मूल्य के संबंध में बकाया राशि की प्रतिशतता निम्नानुसार थी:—

चीनी मौसम	निम्न तारीख को	प्रतिशतता
1993-94	30.9.1994	1.12
1994-95	30.9.1995	2.16
1995-96	30.9.1996	6.97

(घ) सरकार ने पहले से ही सृजित 5 लाख टन चीनी के बफर स्टाक को एक वर्ष तक और बनाए रखने तथा एक वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख टन का अतिरिक्त बफर स्टाक सृजित करने का निर्णय लिया है।

Demand for Secret Ballot for Recognition of Trade Unions

1744. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a demand for introducing secret ballot for recognition of trade unions; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Cretain Central Trade Union Organisations submitted a memorandum to the Prime Minister urging the Government to frame suitable legislation for recognition of trade unions by Secret Ballot. The issue of determination of the representative character of Trade Unions by Secret Ballot has been referred to the Bipartite Committee constituted by the Ministry of Labour and consisting of representatives of employers and workers. Further course of action will depend on the recommendation of the committee.

खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के उपाय

1745. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनिजों के निर्यात में समिति वृद्धि के लिये कौन-कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात हेतु खनिजों के खनन कार्य में निवेश करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु कोई समयबद्ध कदम उठाए है अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) खनिज निर्यात संबंधी राशि में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में इसमें 11% की बढ़ोत्तरी हुई। खनिज क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में भी संशोधन किया गया इससे अनेक क्षेत्रों में निवेश करने में सुविधा होगी जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन करने जिससे खनिज क्षेत्र का विकास होगा और निर्यात-अर्जन में वृद्धि होगी।

Waivers of Anti-Dumping Duties

1746. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the All India Flat Tape Manufactures and All India Plastic Woven Sacks Manufacturers have given some representations for redressal of their grievances on walver of anti-dumping duty by the European Union;

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government have taken any action the matter;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) The All India Flat Tape Manufacturers' Association and Plastic Woven Sacks manufacturers' Association have represented to the Ministry regarding the anti-dumping investigation undertaken by the European Union against imports of plastic woven sacks and bags from India. They have quoted reports about provisional anti-dumping duties having been determined to be imposed on these imports by EU and requested Government to intervenue, through diplomatic and political channels, to ensure that the duty is withdrawn.

(c) to (e) EU has not yet notified anti-dumping duties against imports of plastic woven sacks and bags from India. However, the investigations have been completed. The Government has been appropriately apprising the industry of the progress in the investigations and rendering all possible assistance to them in these investigations. The Government has also taken up the matter at the diplomatic level with the European Commission as well as Individual EU Members and European importers requesting them not to impose anti-dumping duties on this.

जनता के कतिपय वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर निकाला जाना

1747. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण और राशन प्रणाली के कुछ विशेष वर्गों तक सीमित करने का विचार रखती है;

(ख) सरकार जनता के किन वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन प्रणाली से अलग करना चाहती है; और

(ग) क्या इससे मध्यम वर्ग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को विशेष कार्ड जारी कर तथा उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करते हुए सुप्रवाही बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। किसी भी वर्ग को प्रणाली से बाहर करने का प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय विकलांग खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना

1748. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में बनाई गई राष्ट्रीय विकलांग खेल प्रतिस्पर्धा योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत हुई राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Applications for Obtaining Coal Mining leases

1749. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the number of applications received from private/public sector parties desirous of obtaining coal mining leases for captive use, from the date of allowing captive coal mining during the last three years, year-wise;

(b) the number of these coal bearing areas/mining blocks identified and